

बजट में छूट की आस



वित्तीय साल 2024-25 की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में सुखरूप से देश में संभव हुए लोकसभा चुनाव रहा है। वहीं चुनाव से फहले निर्वाचन अयोग द्वारा चुनाव आचार सहित लागू होने के कारण केंद्र सरकार की पूँजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भरकम कर्मी भी बुनियादी रुद्धि है। साथ ही देश में मानसून की स्थिति भी ठीक नहीं रही। केंद्र सरकार ने फिर भी मुद्रा स्फीटि पर अक्षुश लगाने में अधिकतम तो अंजित कर ली, परन्तु उच्च स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि के कारण अम नारायिक, विशेषकर मध्यवर्गीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है और कुछ मध्यवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यानि करने के कारण उनको गरीबी रेखा की ब्रिणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। किसी भी देश में मध्यवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रही है, तो उस देश की अर्थिक विकास दर भी उच्च स्तर पर बनी रहती है, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उच्चायी मसलन चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, फिज, क्लूर, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए पफ्टेट्स एवं भवनों आदि को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग बढ़ा खरीददार करता है। इससे उस देश में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए नए निकलते हैं। भारत में पिछले कछ समय से मध्यवर्गीय परिवारों की व्याप करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। और कुछ मध्यवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यानि करने के कारण उनको गरीबी रेखा की ब्रिणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। किसी भी देश में मध्यवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रही है, तो उस देश की अर्थिक विकास दर भी उच्च स्तर पर बनी रहती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्वत्सा सीतारामण बहुचर्चित विकासित भारत कार्यक्रम के माध्यम से 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने की बात कर रहे हैं।

अइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीनतम रूपों पर नजर डालें। इससे इन कंपनियों की आय एवं लाप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए नए निकलते हैं। भारत में पिछले कछ समय से मध्यवर्गीय परिवारों की व्याप करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस लिए आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्वत्सा सीतारामण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए भी विशेष रूप से आयकर में छूट की घोषणा करेंगी। जिसकी मध्यवर्गीय परिवार आस लगाए बैठी है।

बजट 2025-26 : मांग को बढ़ावा देना व अधिक नौकरियां पैदा करना

नित्य चक्रवर्ती

भा रत सरकार 1 फरवरी 2025

को मोदी शासन के तीव्ररूप कार्यकाल में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे वाली है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विषयाली कार्यकारी कार्यक्रम के कारण व्यापार और वैश्वीकरणीय अविश्वासी के बढ़ावा देने के लिए वृद्धि में वैश्वीकरणीय अविश्वासी के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि में घेरेलू मंदी का महान तैयार है। नवीनतम आधिकारिक अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर अक्षुश लगाने में अंजित तो अंजित कर ली, परन्तु उच्च स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि के कारण अम नारायिक, विशेषकर मध्यवर्गीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है और कुछ मध्यवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यानि करने के कारण उनको गरीबी रेखा की ब्रिणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। किसी भी देश में मध्यवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रही है, तो उस देश की अर्थिक विकास दर भी उच्च स्तर पर बनी रहती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्वत्सा सीतारामण बहुचर्चित विकासित भारत कार्यक्रम के माध्यम से 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने की बात कर रहे हैं।

अइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीनतम रूपों पर नजर डालें। इससे इन कंपनियों की आय एवं लगातार तो अधिकतम भाग का उपयोग बढ़ा खरीददार करता है। इससे उस देश में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए नए निकलते हैं। भारत में पिछले कछ समय से मध्यवर्गीय परिवारों की व्याप करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस लिए आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्वत्सा सीतारामण वर्ष 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए भी विशेष रूप से आयकर में छूट की घोषणा करेंगी। जिसकी मध्यवर्गीय परिवार आस लगाए बैठी है।



भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीनतम रूपों पर नजर डालें। पहला, लोगों का उपभोग पैटर्न और दूसरा, रोजगार सूजन परिदृश्य। ये दोनों मुद्रे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। विकास का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है। यह विकास की गुणवता से संबंधित है और क्या जीडीपी वृद्धि में अतिरिक्त वृद्धि ने देश की आवादी के बड़े हिस्से को मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सामाजिक संकेतकों में वृद्धि के मामले में मदद की है? नेट्रो मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों से अधिक समय में, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे। 2020 और 2021 में महामारी ने गरीबों और मध्यम वर्गों के जीवन स्तर को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसका असर उपभोग पर पड़ा। जैसा कि नवीनतम धरोहर के लिए वृद्धि लगाया गया था, वित्त मंत्री निर्वत्सा सीतारामण वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे। 2020 और 2021 में महामारी ने गरीबों और पूर्वोत्तर विशेष वर्गों के जीवन स्तर को बड़े हिस्से को मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सामाजिक संकेतकों में वृद्धि के मामले में मदद की है? नेट्रो मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों से अधिक समय में, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे। 2020 और 2021 में महामारी ने गरीबों और पूर्वोत्तर विशेष वर्गों के जीवन स्तर को बड़े हिस्से को मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सामाजिक संकेतकों में वृद्धि के मामले में मदद की है? नेट्रो मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों से अधिक समय में, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे। 2020 और 2021 में महामारी ने गरीबों और पूर्वोत्तर विशेष वर्गों के जीवन स्तर को बड़े हिस्से को मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सामाजिक संकेतकों में वृद्धि के मामले में मदद की है? नेट्रो मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों से अधिक समय में, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे। 2020 और 2021 में महामारी ने गरीबों और पूर्वोत्तर विशेष वर्गों के जीवन स्तर को बड़े हिस्से को मजदूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सामाजिक संकेतकों में वृद्धि के मामले में मदद की है? नेट्रो मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों से अधिक समय में, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त अंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लगाया 5.4 प्रतिशत है और पूरे वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। यह भारत के विकास पथ पर एक बड़ा स्तर पर रही मुद्रा स्फीटि पर जोर दिया गया। ग्रामीण और शहरी गरीबों तक धन पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं थे

